भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2614
दिनांक 23.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत द्वारा नेपाल में किए गए विकास कार्य

2614. श्री सतीश चंद्र दूबे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत नेपाल के विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत द्वारा नेपाल में कौन–कौन सी विकासात्मक/ अन्य परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए नेपाल पर किए गए व्यय और उसे सहायता के रूप में प्रदान की गई निधि का वर्ष वार और परियोजना–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत भारतीय कामगारों की संख्या कितनी है और उनकी सुरक्षा के लिए नेपाल सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी क्या प्रबंध किए गए हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क से ग) भारत सरकार की पड़ोस प्रथम नीति के अनुरूप, भारत का नेपाल के साथ मजबूत विकास सहयोग है, जिसके तहत कई संपर्क, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, और कई अन्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। भारत नेपाल के विभिन्न जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ग्रामीण अवसंरचना और आजीविका विकास के प्रमुख क्षेत्रों में उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नेपाल को वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय के 'नेपाल को सहायता' बजट शीर्ष, जिसके माध्यम से विकास सहयोग कार्यक्रम चलाए जाते हैं, में आबंटित अनुदान का विवरण इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	'नेपाल को सहायता' बजट आबंटन (आईएनआर)
i.	2019–20	1200 करोड़
ii.	2020–21	880 करोड़
iii.	2021–22	550 करोड़
iv.	2022–23	425 करोड़

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत द्वारा नेपाल में भारत सरकार की सहायता से निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं को पूरा किया गया है:

(i) वित्तीय वर्ष 2019–20 में 139.73 करोड़ रुपये की लागत से जनवरी 2020 में नेपाल के बिराटनगर में एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण पूरा किया गया और इसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा, सितंबर 2019 में भारत में मोतिहारी से नेपाल में अमलेखगंज तक दक्षिण एशिया में पहली सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन [मैसर्स आईओसीएल द्वारा वित्त पोषित] शुरू की गयी थी।

(ii) वित्तीय वर्ष 2020–21 में मार्च 2021 में 14 में से 9 तराई सड़क पैकेजों को नेपाल सरकार (जी ओ एन) को सौंप दिए गए थे।

(iii) वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार की भूकंप पुनर्निर्माण सहायता के भाग के रूप में, नेपाल के गोरखा और नुवाकोट जिलों में 50,000 घरों का निर्माण पूरा किया गया और नवंबर 2021 में लाभार्थियों को सौंप दिया गया। परियोजना की कुल लागत 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर (100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान और 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता सहित) है।

(iv) वर्तमान वित्त वर्ष में, जयनगर–बरदीबास सीमा पार रेल लिंक के जयनगर–कुरथा खंड को शुरू कर दिया गया है और अप्रैल 2022 में भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।
पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान नेपाल में भारत द्वारा निष्पादित प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

(i) 364.85 करोड़ रुपये और 548 करोड़ रुपये की लागत से जोगबनी (भारत)–बिराटनगर (नेपाल) और जयनगर (भारत)–बरदीबास (नेपाल) में 02 सीमा पार लिंकों को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ii) 39.72 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से रक्सौल और काठमांडू के बीच नई ब्रॉड गेज रेल लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(iii) 500 करोड़ रुपये की लागत से तराई सड़कों का उन्नयन किया जा रहा है। सभी पैकेज पूरे हो गए हैं और 14 में से 9 पैकेज नेपाल सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिए गए थे;

(iv) नेपाल में नेपालगंज और भैरहवा में एकीकृत चेक पोस्ट क्रमशः 147.12 करोड़ रुपये और 161.75 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(v) हेटौडा में नेपाल–भारत मैत्री पॉलिटेक्निक लगभग 39 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन है;

(vi) नेपाल के पनौती में 625 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का निर्माण कार्य चल रहा है;

(vii) 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान घटक के साथ भूकंप के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है।

भारत सरकार ने अनुदान सहायता के अलावा सड़क, सिंचाई, जल विद्युत जैसी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण के लिए 1.65 बिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता प्रदान की है।

(घ) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में लगे भारतीय श्रमिकों की संख्या इन परियोजनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार समय–समय पर बदलती रहती है। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर नेपाल सरकार द्वारा यथोचित उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाती है।

*****